ड़क, रेल और हवाई यात्रा में विकास व सुरक्षा की खाई पाटे सरकार

ली: वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण जब वर्ष -27 का आम उजट पेश करेंगी, तब देश का वधन नए एक्सोसरवे, वंदे भारत ट्रेनों और हवाई



अड्डों के विस्तार पर नहीं बल्कि इन ढांचागत सुविधाओं की सुरक्षा पर भी

हिए। बीते वर्षों में सड़क, रेलवे और विमानन में निवेश अभूतपूर्व रहा है। लेकिन इसके तर यात्रा को सुरक्षित बनाने की रफ्तार उस ाज नहीं दिखती। पिछले कुछ वर्षों में सड़क ओं में बढ़ती मौतें, रेल हादसों की आशंका मान निगरानी तंत्र पर उठते सवाल यह देते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अब सुरक्षा के बिना अधूरा है। बजट 2026-27 सरकार यह अवसर है कि वह विकास और सुरक्षा की इस खाई को पाटे और स्मार्ट निवेश व न बदलाव करे ताकि हम एक सुरक्षित भारत र बढ़ें।

जयप्रकाश रंजन • जागरण

क्यों जरूरी है सुरक्षा को प्राथमिकता देना

सड़क : 2023 में सड़कों पर 1.72 लाख मौतें हुईं, जो रोजाना औसतन 470 मौतें के बराबर हैं। इस वर्ष 4.8 लाख दुर्घटनाएं हुईं। आंकड़े बताते हैं कि दुर्घटना की संख्या 80 प्रतिशत बढ़ी है लेकिन मौतों की संख्या 80 प्रतिशत बढ़ी है। यानी दुर्घटनाएं ज्यादा घातक हो रही हैं। ऐसे मुख्य कारण ओवरस्पीडिंग (71 प्रतिशत मौतें), शराब पीकर ड्राइविंग, गलत दिशा में चलना और हेलमेट/सीट बेल्ट न पहनना हैं। सड़कों की गुणवत्ता भी एक प्रमुख कारण है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारों के स्तर पर इन मौतों को कितना सहज से रोका जा सकता है? जानकारों का कहना है कि हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्र नियमों, नीतियों व कानूनों के जरिए एक बानगी पेश कर सकता है। यही रास्ते की सुरक्षित यात्राओं को सुनिश्चित देने का दबाव बना सकता है। केंद्र की पहल पर पूरे देश में स्मार्ट निगरानी या एआइ आधारित ट्रैफिक नियंत्रणी प्रणाली को अपनाने की नीति लागू की जा सकती है। हेलमेट और सीटबेल्ट अनुपालन की तकनीकी निगरानी को भी मजबूत किया जा सकता है। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस नेटवर्क के राष्ट्रीय क्रियान्वयन को भी जरूरी माना जा रहा है ताकि बचाव टीम को देरी के कोने-कोने में दुर्घटना-स्थल तक जल्दी पहुंचने को आसान बनाया जा सके।



रेलवे : आंकड़ों में भारतीय रेलवे में दुर्घटना की संख्या कम हुई है। 1960 के दशक में सालाना 1,390 दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनकी संख्या घटकर अब करीब 80 पर सिमट गई है। लेकिन वर्ष 2023 में 48 गंभीर हादसे हुए। रेलवे बड़ा कारण बॉगियों का डिरेलमेंट यानी पटरी से उतरना है। 55 प्रतिशत से ज्यादा दुर्घटनाओं के लिए मानवीय गलतियों को जिम्मेदार माना गया।

1.72 लाख मौतें हुईं थीं कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान पूरे देश में सड़क हादसों के कारण, उस वर्ष 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं

71% मौतें ओवरस्पीडिंग के कारण होती हैं सड़क हादसों में, शराब पीकर या गलत सड़क ड्राइविंग और हेलमेट न पहनना भी प्रमुख कारण

विमानन : अगर एविएशन की बात की जाए तो मे 2025 का एअर इंडिया विमान एआइ-171 दुर्घटना (260 मौतें) जैसे हादसे हुए, जिससे जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। दिसंबर, 2025 में भारतीय एविएशन सेक्टर में तकरीबन 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो की एक साथ सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से जो हालात पैदा हुए, उसने नियमन संबंधी कमजोरियों को बेहद ला दिया है।

कौन-कौन से कदम उठाए जाने चाहिए

- आम बजट में सभी प्रमुख मार्गों पर कवच और सीबीटीसी जैसे इनलैंड ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के विस्तृत विस्तार की घोषणा कर यात्रा को सुरक्षा बनाने का भरोसा दिलाया जाए
- कवच के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा होनी चाहिए
- रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रेन न एआइ के इस्तेमाल को लेकर भी महत्वाकांक्षी कदम उठाए जाएं
- डीजीसीए को अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करने की घोषणा करके इस सेक्टर में जवाबदेही सुनिश्चित लाई जाए
- भारत को विमानन क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने के लिए विमान रखरखाव व मरम्मत नेटवर्क को लेकर अलग से विशेष योजना की घोषणा करनी चाहिए

दूसरे देशों से सीखने की जरूरत

दुनिया की बीची सबसे बड़ी इकोनमी बनने के साथ ही सड़क सेक्टर की मांग साफ है कि आने वाले वर्षों में अभी सड़क, रेलवे व हवाई नेटवर्क पर भारी भरकम निवेश हो। यहां सरकार चाहे तो चीन व जापान से काफी कुछ सीख सकती है, जहां सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार टेकनोलजी आधारित समाधान पर काम किया जा रहा है। चीन की हाई-स्पीड रेल (60,809 किमी नेटवर्क) में मौतें बहुत कम होती हैं क्योंकि ड्रेक संचालन, अग्रिम सिग्नलिंग और नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। भारत में जहां दो प्रतिशत सड़कें 36 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, वहीं चीन ने एक्सप्रेसवे नेटवर्क का जाल बिछाने के बावजूद दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया है। जापान में भूकंप अलर्ट वार्निंग सिस्टम देने की पहले रोक देता है। यूरोप और अमेरिका में पाजिटिव ट्रेन कंट्रोल (पीटीसी) से दुर्घटनाओं में 80 प्रतिशत कमी की गई है। यूरोप में यात्री प्रति किमी पर मौतें भारत से 10 गुना कम है, क्योंकि सख्त कानून प्रवर्तन है। इन सभी देशों में केंद्रीय कानून व तहत सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन होता आया है। भारत में जहां दो प्रतिशत सड़कें 36 प्रतिशत

2025 में 117 लाख करोड़ बढ़ी पारिवारिक सम्पत्ति

पिछले वर्ष के दौरान भारतीय परिवारों की सम्पत्ति बढ़ने में सोने की कीमतों में तेजी का प्रमुख योगदान

नई दिल्ली, आशुलाभ: कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान भारतीय परिवारों की संपत्ति में एक महत्वपूर्ण वृद्धि रही है। यह मुख्य रूप से सोने की कीमतों के तेज बढ़ोतरी के कारण हुई है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ईयरबुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान भारतीय परिवारों की संपत्ति में 117 लाख करोड़ रुपये या करीब 1.3 ट्रिलियन डालर की वृद्धि हुई है। इससे परिवारों के लिए एक मजबूत खर्च करने की क्षमता बनी है। इस हाउस ने बताया कि यह पिछले 25 वर्षों में सोने की कीमतों में वृद्धि से होने वाला सबसे बड़ा संपत्ति लाभ है। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान सोने की कीमत में 58,310 रुपये प्रति 10 ग्राम या 73.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तेज वृद्धि ने एक मजबूत सकारात्मक संपत्ति प्रभाव उत्पन्न किया है, जिसमें सोने के खिलाफ खुदरा कर्ज (गोल्ड लोन) में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 भारतीय शेयर बाजारों के लिए एक समेकन का वर्ष साबित हुआ, जबकि सोने जैसे वैकल्पिक संपत्तियों ने असाधारण ताकत दिखाई। पिछले वर्ष सोना स्पष्ट रूप से एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में उभरा, जबकि शेयरों पर दबाव था। 2025 के दौरान वैश्विक बाजारों में भी भारत का प्रदर्शन खराब रहा, जिसके कारण वैश्विक बाजार पूंजीकरण में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट आई। निफ्टी ने वैश्विक समकक्षों और उभरते बाजारों की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत कम प्रदर्शन किया, जो लगभग तीन दशकों में इसका सबसे खराब प्रदर्शन है।

- पिछले वर्ष के दौरान 58,310 रुपये बढ़ा सोने का मूल्य
- कीमत बढ़ने के कारण गोल्ड लोन में भी वृद्धि दर्ज की गई
- तेल, डालर और बिटकाइन का खराब प्रदर्शन रहा



73 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया सोने ने पिछले वर्ष के दौरान

25 प्रतिशत से कम रहा निफ्टी का प्रदर्शन समकक्षों की तुलना में

हाइब्रिड फंड पर विचार कर सकते हैं निवेशक

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई वर्षों की मजबूत वृद्धि के बाद छोटे और मिड-कैप शेयरों ने 2025 में लार्ज-कैप शेयरों की तुलना में कम प्रदर्शन किया है, जबकि बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन तेज हुआ है। लार्ज-कैप शेयर अभी भी बेहतर मूल्य प्रदान कर रहे हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने सलाह देते हुए कहा है कि निवेशक पोर्टफोलियो की अस्थिरता को कम करने के लिए हाइब्रिड फंड पर विचार कर सकते हैं। ऐसे फंड निवेशकों को शेयर, डेट और सोने के मिश्रण से लाभ उठाने की अनुमति देते हैं, जो अनिश्चित आय स्थितियों में बेहतर संतुलन प्रदान करते हैं।

इस सुधार ने भारत के मूल्यांकन प्रीमियम को इसके दीर्घकालिक औसत के करीब ला दिया है। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान वैश्विक स्तर पर सोना, उभरते बाजार, यूरोप और शानदार-7 शेयर शीर्ष प्रदर्शन करने वाली में थे। इसके विपरीत, तेल, अमेरिकी डालर और बिटकाइन वर्ष के दौरान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों में रहे। शानदार-7 में एपल, माइक्रोसाफ्ट, एमेजोन, अल्फाबेट, मेटा, एनवीडिया और टेस्ला के शेयर शामिल हैं। यह सातों दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली टेकनोलजी कंपनियों हैं और अमेरिका के प्रमुख सूचकांक एसएंडपी 500 और कुल बाजार में इनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

तीन वर्षों में ईयू को दोगुना हो जाएगा निर्यात

नई दिल्ली, क्षेत्र: निर्यातकों का कहना है कि भारत और 27 देशों के संगठन यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने से वस्त्र, फार्मास्युटिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, रत्न व आभूषण के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। समझौते के लिए वार्ता के समाप्त की घोषणा 27 जनवरी को की जा सकती है। उद्योग का अनुमान है कि एफटीए के कारण टैरिफ समाप्त होने से अगले तीन वर्षों में ईयू को निर्यात दोगुना हो जाएगा।

निर्यातकों ने बताया कि यह एफटीए निर्यात के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित ढांचा प्रदान करेगा, जिससे भारतीय कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश योजना बनाने, यूरोपीय मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अप्रैल एफएसटी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए शक्तिवेल का कहना है कि यह एफटीए किसी एक बाजार पर हमारी निर्भरता को कम करने में एक गेम चेंजर होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए ज्यादा टैरिफ के कारण घरेलू निर्यातकों को उच्च लागत और एक प्रमुख बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारतीय निर्यातकों को निर्यात बाजार में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है।

तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का लाभ 12 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई, क्षेत्र: निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के दौरान उसका कुल लाभ 12.17 प्रतिशत बढ़कर 19,807 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान बैंक को 17,657 करोड़ रुपये और जुलाई-सितंबर 2025 में 19,611 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि बीती तिमाही में उसकी ब्याज से शुद्ध आय 6.4 प्रतिशत बढ़कर 32,60 करोड़ रुपये और गैर-ब्याज से आय 13,250 करोड़ रुपये रही है। इस दौरान शुद्ध ब्याज लाभ 3.35 प्रतिशत रहा है। तिमाही के दौरान नए लेबर कोडों के कार्यान्वयन से बैंक पर 800 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। उधर, कम प्रोविजन के कारण बीती तिमाही में यस बैंक का लाभ 55 प्रतिशत बढ़कर 952 करोड़ रुपये रहा है।

- बीती तिमाही में बैंक को 19,807 करोड़ रुपये का लाभ
- आइसीआइसीआइ बैंक को 12,537 करोड़ रुपये का लाभ

आइसीआइसीआइ बैंक का लाभ 2.68 प्रतिशत घटा

आइसीआइसीआइ बैंक ने कहा है कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 2.68 प्रतिशत घटकर 12,537.98 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष समान तिमाही में बैंक को 12,883.37 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बैंक ने बताया कि बीती तिमाही में उसका से शुद्ध आय 7.7 प्रतिशत बढ़कर 21,932 करोड़ रुपये रही है और गैर-ब्याज आय में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नए लेबर कोड लागू करने से बैंक पर 145 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। साथ ही प्रोविजन 2,556 करोड़ रुपये रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता
www.rbi.org.in
निर्गम विभाग, 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001
फोन - 033-2213 0684, ई-मेल: ikbollata@rbi.org.in

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

1.भारतीय रिज़र्व बैंक: कोलकाता निम्नलिखित कार्यों के लिए दो भागों (भाग-I और भाग-II) में ई-निविदाएं आमंत्रित करता है:

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ में) वित्तीय वर्ष 2026-27 और वित्त वर्ष 2027-28) के लिए
1	बैंक में दिन प्रति दिन नए सिक्कों (खाता के जोड़ित के साथ-साथ) कोटेशन आधारित सिक्कों के प्रसंस्करण के लिए स्वचालित मशीनों की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग और उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण	₹26.04 करोड़
2	सिक्कों के लिए ऑटो बंडलिंग के लिए मशीनों की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग और उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण	₹1.81 करोड़

1.पात्रता के पूर्व विवरण के साथ-साथ भाग I और भाग - II के साथ दोनों निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए, कृपया निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx या
https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi
2. एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा जारी होने की तिथि: 18 जनवरी, 2026 10:00 बजे। निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 09 फरवरी, 2026, 13:00 बजे
3. बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
नोट: उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा

क्षेत्रीय निदेशक
प्रदीप कुमार और अजय व पिनाकेश द्वीप समूह

पृष्ठ के शेष...

कायदा मिलेगा। हालांकि, सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा को इस दायरे में लाने का है। इस योजना की रूपरेखा स्टीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि)' की तर्ज पर जा रही है, जिसके माध्यम से किफायत रेहड़ी-पटरी वाली यशोदा कुमार पंजीकृत हो चुके थे। **बेदाग लाभार्थी को क्रेडिट कार्ड** : सरकार का लक्ष्य पूरा 1.15 करोड़ लोगों को ना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे। योजना की मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है और इसके लिए 7,332 करोड़ जट निर्धारित किया गया है। समय पर ऋण ऋण चुकाने वाले को यूपीआइ से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड देने की भी योजना है। रा अब कस्बों के साथ अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया

अभियान आयोजित किए जा सकते हैं जो केंद्र और राज्यों के नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार के आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान-प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और रिक्तियों को चार महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन पदों को रिक्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर भर जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुछ सेवानिवृत्ति की तिथि पहले से पता होती है इसलिए, भर्ती प्रक्रिया कम्बी पहले शुरू हो जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे पद एक महीने से ज्यादा समय तक रिक्त न रहें। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को सालाना रिपोर्ट देंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि कितने आरक्षित पद रिक्त हैं, कितने भरे गए, न भरने के कारण और कितना समय लगा। ताकि समय-समय पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। कोर्ट ने छात्रवृत्तियों के भुगतान में देरी और कई बार सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोकने जैसी की घटनाओं पर भी संज्ञान लिया है, क्योंकि इससे कमजोर तबके छात्रों को नुकसान होता है। साथ ही आदेश दिया कि सभी लंबित छात्रवृत्तियों का बकाया भुगतान संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा चार महीने के भीतर किया जाए। यदि भुगतान न होने का कोई कारण हो तो संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान और छात्र को दो महीने के भीतर कारण सहित सूचना भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में दी जाने वाली सभी छात्रवृत्तियों का वितरण संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा स्पष्ट समय सीमा के भीतर और बिना किसी देरी के किया जाए। **उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग को लेकर कड़ी चेतावनी** : शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग रोकने के बारे में आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को विशेष रूप से यह कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे उन सभी नियमों का पूरी- पालन करें जो उन पर बाध्यकारी हैं, जिनमें यूजीसी का उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने संबंधी रेगुलेशन, 2009, यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन 2012, यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) रेगुलेशन 2016, यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) रेगुलेशन 2023, आदि शामिल हैं। इसके अलावा विशेष रूप से रैगिंग विरोधी समितियों और रैगिंग रोधी दस्तों, भेदभाव रोधी अधिकारियों, आंतरिक शिकायत समितियों और छात्र शिकायत निवारण समितियों की स्थापना और संबंधित शिकायत निवारण तंत्रों के लिए नियुक्त प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यदि कोर्ट ने छात्रों को सुरक्षित वातावरण देने की बात करते हुए ऊपर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी छात्र की आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
क्षेत्रीय कार्यालय झाँसी क्षेत्र : भूमितल, नगर निगम बिल्डिंग इलाइट चौराहा, जिला–झाँसी–284001 (उ.प्र.)
अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए विक्रय सूचना "अनुर्नत-IV-A (नियम 8(6) के प्रावधान देखें) | शाखा : इलाइट चौराहा, झाँसी

वहाँ उपलब्ध है

विनम्र निवेदन व शर्तों हेतु देखें

ई-नीलामी की तिथि : 27.02.2026 | ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 26.02.2026, सायंकाल 4:00 बजे तक

जारीगर्ता / उधारकर्ताओं का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण, आक्षत अतिक्रमण यदि कोई हो तो	सुरक्षित राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ भिन्न बढ़ोतरी राशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक/ भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय
कब्जेदार : मेसर्स भवोदिया इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी, **पार्टनर :** श्री सन्दीप सिंह भदोरिया एवं श्री हितेन्द्र भदोरिया, पते:- (1) अधिकृत एवं